

>

Title: Need to promote the use of Hindi language in Government Offices and Departments.

श्री छर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प.): राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिवर्ष छिन्दी भाषा में सरकारी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए समितियों का गठन किया जाता है तथा प्रतिवर्ष छिन्दी परखवाड़ा भी मनाया जाता है जिस पर सार्वजनिक धन का व्यय होता है। इन सारे प्रयासों के बाद भी छिन्दी भाषा में सरकारी कामकाज बढ़ने के स्थान पर कम होता जा रहा है।

राजभाषा छिन्दी के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बनाए गए राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का पालन केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, उसके नियंत्रण के निम्नमें एवं कंपनियों द्वाया नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति यहां तक पहुंच नहीं है कि सांसारिक द्वाया छिन्दी में लिखे पत्रों का उत्तर भी उन्हें अंग्रेजी में दिया जा रहा है।

ऐसी दशा में राजभाषा को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने हेतु संविधान एवं राजभाषा अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों को बढ़ावा से लानु किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इन प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों के विश्वदृष्टि प्रभावी कार्यवाही भी राजभाषा छिन्दी को संरक्षित करने की दृष्टि से आवश्यक है।